बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 283

मुद्रास्फीति की चिंता

मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़ों ने देश में आर्थिक नीति निर्माण की जटिलता को बढ़ा दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 7.35 फीसदी हो गई। इस तरह उसने भारतीय रिजर्व बैंक के 2 से 6 फीसदी के दायरे को भी लांघ लिया। खाद्य मुद्रास्फीति 14.12 फीसदी रही जबकि इससे पिछले माह यह 10.01 फीसदी थी। इसके लिए सब्जियों और दालों की बढ़ी हुई कीमत उत्तरदायी थी। खुदरा महंगाई ने ऐसे वक्त तय लक्ष्य का उल्लंघन किया है जब वृद्धि में तेजी से धीमापन आया था। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7.5 फीसदी की नॉमिनल दर से बढ़ने की उम्मीद है।

नीतिगत दरों में 135 आधार अंकों की कमी करने के बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर में ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का एकदम उचित निर्णय लिया है। ऐसा मोटे तौर पर मौद्रिक नीति संबंधी जोखिम के कारण किया गया। मौद्रिक नीति के अलावा खुदरा मुद्रास्फीति में इजाफा 2020-21 के बजट को भी प्रभावित करेगा। कम मुद्रास्फीति राजग सरकार की उपलब्धियों में से एक रही है। ऐसे में आगामी बजट में धीमी आर्थिक वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति दोनों को साधना आसान नहीं होगा।

बजट प्रस्तुत होने के कुछ दिन बाद एमपीसी मौद्रिक नीति की दिशा स्पष्ट करेगी। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि खाद्य वस्तुओं में उच्च मुद्रास्फीति अस्थायी है और आने वाले महीनों में इसमें कमी आएगी। एमपीसी को और सतर्कता बरतनी होगी। मूल मुद्रास्फीति जहां सहज स्तर पर है, वहीं ताजा शीर्ष मुद्रास्फीति के आंकड़े फरवरी की बैठक में दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की संभावना खारिज करते हैं।

बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि आखिर एमपीसी कब तक दरों को लंबित रखेगी। दो बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली, आरबीआई के मई 2019 के एक शोध पत्र में कहा गया कि मुद्रास्फीति के व्यापक अनुमानों में चूक होती है क्योंकि खाद्य कीमतों से लगने वाले झटकों का अंदाजा नहीं होता। खासतौर पर सब्जियों जैसी खराब होने वाली चीजों की कीमतों का।

पूरे देश से मिलने वाले प्रमाण यही सुझाव देते हैं कि अनुमान में कमियों का संबंध खुदरा मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों के भार से है। चूंकि बीते सालों में खाद्य कीमतों में गिरावट के अनुमान नहीं लगाए जा सके इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसमें इजाफे के अनुमान लगाने में भी कठिनाई होगी। दूसरी बात, यदि आरबीआई लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति के लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा तो उसे केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसमें उसे नाकामी के कारण बताने होंगे और प्रस्तावित कदमों का जिक्र करना होगा। यह भी बताना होगा कि वह कितने समय में लक्ष्य को हासिल करेगा। जाहिर है केंद्रीय बैंक ऐसी स्थिति से बचना चाहेगा।

मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले ढांचे के कारण आने वाले महीनों में आरबीआई बड़ी परीक्षा भी होने वाली है। इस संदर्भ में यह देखना अहम होगा कि आखिर आरबीआई किस हद तक अपने मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान बदलता है और निकट भविष्य में खाद्य कीमतें कैसा व्यवहार करती हैं। भारतीय स्टेट बैंक का एक शोध बताता है कि सब्जियों की मुद्रास्फीति में इजाफा होने के दो महीने बाद प्रोटीन की महंगाई में इजाफा होता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक खाद्य कीमतों में भी अहम इजाफा हुआ है। ऐसे में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के जोखिम के साथ मौद्रिक नीति आगामी तिमाहियों में वृद्धि को सहारा देने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार पर होगी। इसका खाका बजट में सामने आना चाहिए।

बिनय सिन्हा

2020 में भी रहेगा 2019 की घटनाओं का असर

वर्ष 2019 की घटनाओं का धुंधलका भारत और पूरे विश्व पर और अधिक गहरा होता जाएगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **शंकर आचार्य**

वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर सन 2020 कैसा साबित हो सकता है? इस सवाल के जवाब की तलाश करते हुए मैं अनिश्चितता और अपर्याप्त जानकारी के धुंध को पार करने का प्रयास करता हूं तो हालिया समाप्त वर्ष 2019 की लंबी छायाएं मेरी राह रोक लेती हैं। सन 2019 न तो वैश्विक सहयोग के लिए, न ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और न ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर वर्ष था।

वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक सहयोग

वैश्विक सहयोग के संपूर्ण फलक को देखें तो सन 2019 में भारी गिरावट देखने को मिली। व्यापक तौर पर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 2017 के बाद से नीतियों में लगातार बदलाव किए और उनकी बदौलत अंतरराष्ट्रीय मामलों में एकपक्षीय रुख आया। इसके अलावा बहुपक्षीय सहयोग और संधियों तथा संस्थानों के मामलों में भी उन्होंने निरंतर बदलाव किए। तीन उदाहरणों पर विचार करना आवश्यक है।

पहला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत की बात करें तो ट्रंप ने चीन, यूरोप और कुछ अन्य देशों के खिलाफ कारोबारी जंग की शुरुआत की। यह जंग जारी है और इसका असर वैश्विक व्यापार, निवेश और वृद्धि पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि चीन के साथ संभावित पहले चरण के समझौते से लाभ मिल सकता है लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस हद तक होगा। विश्व व्यापार संगठन की विवाद निस्तारण वाली अपील संस्था में नियुक्तियों को व्यवस्थित तरीके से बाधित करके अमेरिकी प्रशासन ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दिसंबर 2019 में यहां सात के बजाय केवल एक न्यायाधीश रह गया। इससे हुआ यह कि सदस्यों के बीच विवादित मसलों पर निर्णय के लिए अनिवार्य न्यूनतम तीन न्यायाधीश भी नहीं रह गए। अपील संस्था का कामकाज ठप हो गया और विश्व व्यापार अप्रत्याशित और खतरनाक रूप से ऐसी स्थिति का शिकार हो गया जहां विवाद निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं रही। इसका नकारात्मक असर 2020 में और आगे देखने को मिलेगा।

दूसरा, सन 2015 में जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते से अब तक कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम हासिल नहीं हुए हैं। यकीनन जलवायु परिवर्तन की स्थिति निरंतर बिगड़ रही है। एक बार पुन: अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस बात का दोषी है कि उसने जून 2017 में अमेरिका के एकतरफा ढंग से बाहर निकलने का नोटिस दिया और अपनी नीतियों तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में असहयोग के जरिये समझौते की भावना के प्रतिकूल काम किया। गत माह मैड्रिड में ऐसे ही एक सम्मेलन का आयोजन किया गया लेकिन वहां भी कोई प्रगति नहीं हुई। कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के परिणामों के बारे में सर्वव्यापी रिपोर्ट होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। लब्बोलुआब यह कि हम सन 2100 तक वैश्विक ताप में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की दिशा में बढ़ रहे हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक रोकने की बात है।

तीसरा और सबसे अहम वैश्विक कृत्य है वैश्विक शांति जो 2019 में अमेरिका और रूस के बीच सन 1987 की एक संधि समाप्त होने के बाद से ही दबाव में है। इसके अलावा सामरिक हथियार कम करने संबंधी नई संधि को विस्तार नहीं मिल पाने, उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम को सीमित रखने पर सहमति नहीं बन पाने और ईरान तथा अमेरिका (और उसके सहयोगियों इजरायल और सऊदी अरब) के बीच बढ़ते तनाव ने भी इसमें योगदान किया है। अमेरिका मई 2018 में 2015 की कई देशों वाली ईरान परमाणु संधि से एकपक्षीय रूप से अलग हो गया और उसने ईरान पर कई प्रतिबंध थोप दिए। पिछले दिनों अमेरिका द्वारा ईरान के एक शीर्ष जनरल की हत्या ने सन 2020 में पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष की राह प्रशस्त की है।

विश्व अर्थव्यवस्था

सन 2019 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि घटकर 2.5 फीसदी रह गई। ऐसा तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की वजह से हुआ। 21 लाख करोड़ डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 2.4 फीसदी रह गई जबकि 19 लाख करोड़ डॉलर की यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था 1.5 फीसदी और 14 लाख करोड़ डॉलर की चीनी अर्थव्यवस्था 6.1 फीसदी पर रही। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में इन तीनों की हिस्सेदारी 60 फीसदी है। मंदी की बड़ी वजहों में अमेरिका में कर कटौती प्रोत्साहन में कमी, कारोबारी जंग, चीन का बढ़ता कर्ज और यूरोपीय संघ के वृद्धि के इंजन जर्मनी में आया धीमापन शामिल हैं।

अमेरिका और चीन में लगातार धीमापन आने और यूरोपीय संघ में मामूली बदलाव के अनुमान के बावजूद अक्टूबर 2019 में आईएमएफ के वैश्विक पूर्वानुमान में कहा गया कि 2020 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर मामूली सुधरकर 2.7 फीसदी रहेगी। इसके लिए कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर प्रदर्शन की संभावना को वजह बताया गया है। इनमें ब्राजील, मैक्सिको, तुर्की भारत और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। परंतु पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के साथ अब ये संभावनाएं धूमिल दिख रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है 2020 में वैश्विक वृद्धि 2019 से कमतर रह सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

सितंबर 2019 तक की छह तिमाहियों में देश की आर्थिक वृद्धि 8 फीसदी से गिरकर 4.5 फीसदी रह गई। सन 2019-20 के पूरे वर्ष के लिए यह 5 फीसदी रह सकती है जो पूरे दशक का सबसे निचला स्तर है। आधिकारिक आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। मंदी की वजहों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। इसमें वित्तीय क्षेत्र में तनाव और सरकारी उधारी शामिल हैं जिनके कारण निजी निवेश और खपत में कमी आई। प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी कम हुई है, विनिर्माण कम हुआ है और प्रमुख सेवा क्षेत्रों मसलन दूरसंचार, विमानन और बिजली आदि में समस्याएं सामने आई हैं।

वृद्धि में हालिया गिरावट के पहले रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़ों ने बताया कि रोजगार की स्थिति खस्ता है। बीते दो वर्ष में मंदी बढ़ने के कारण हालात और खराब हुए हैं।

उत्पादन और रोजगार में सुधार की बहुत अधिक संभावना नहीं नजर आती। नीतिगत और संस्थागत बाधाएं भी राह का रोड़ा हैं। सन 2020 में संभावना यही है कि आर्थिक वृद्धि 5 फीसदी के आसपास बनी रहेगी। परंतु यदि पश्चिम एशिया में विवाद बढ़ता है तो इसमें काफी कमी आ सकती है।

(लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर और देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

खूब नजर आने वाले कारोबारियों की सुनाई नहीं देती आवाज

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

भारत में कारोबार की स्थिति में कुछ बातें अवास्तविक हैं और पिछले सप्ताह मंगलवार के समाचारपत्रों से बेहतर इसे कुछ भी बयां नहीं कर पाता है। समाचारपत्रों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के भीतर घुसकर मारपीट करने वाले नकाबपोश गुंडों के हमले से जुड़ी खबरें छाई हुई थीं। इन तस्वीरों के ठीक उलट एक और तस्वीर छपी थी जिसमें प्रधानमंत्री के साथ खड़े उद्योगपतियों का एक समूह नजर आ रहा था। ये सभी पुरुष एवं बुजुर्ग उद्योगपति अर्थव्यवस्था को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में शामिल थे।

पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड हस्तियों के एक तबके ने जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित होने और जल्द ही देश भर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की घोषणा भी विवादों में है। ये दोनों मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन उन्हें एक साथ जोड़कर नागरिक समाज के खिलाफ निष्ठुर बहुसंख्यकवाद के विरोध की बुलंद आवाज बना दिया गया है।

वैसे यह अजीब है कि किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि हमारा कारोबारी समुदाय दिखाई देने के बावजूद सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? आखिरकार भारत के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनकी पहुंच किसी भी अभिनेता, लेखक, गायक या डांसर से कहीं अधिक है।

गत 12 दिसंबर को सीएए पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने के साथ ही देश भर में विरोध भड़क उठे थे। उसके बाद से प्रधानमंत्री कारोबारियों से समूह या व्यक्तिगत तौर पर कम-से-कम तीन बार मिले हैं। गत 20 दिसंबर को उन्होंने उद्योग मंडल एसोचैम के सम्मेलन को संबोधित किया। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री ने 60 उद्यमियों एवं कारोबारी दिग्गजों से मुलाकात की, फिर 6 जनवरी को वह उद्योग जगत के दिग्गजों के एक और समूह से मिले।

आखिरी मुलाकात तो जेएनयू में हुई हिंसा के चंद घंटों बाद ही हुई थी। इस समूह में शामिल केवल एक उद्योगपति ने सार्वजनिक तौर पर अपनी राय रखी थी लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इसे उठाया या नहीं। वह आनंद महिंद्रा थे जिन्होंने एक ट्वीट में इसका जिक्र किया था। खुलकर अपनी बात कह चुके उद्योगपति इस मंत्रमुग्ध जमात से बाहर ही रहे लेकिन उन्होंने हिंसा की साधारण निंदा ही की। केवल हर्ष गोयनका ही पूरे साहस से कह पाए कि 'धार्मिक जंगल की आग ने पूरे देश को आगोश में ले रखा है'। इसे सत्तारूढ़ पार्टी के शासन एजेंडा की सीधी आलोचना माना गया। नौशाद फोर्ब्स ही अपने लेखों के जरिये कारोबारी समुदाय की नीति-निरपेक्ष चुप्पी का अपवाद बने रहे हैं।

चलिए, मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों को संदेह का लाभ दे देते हैं। शायद उन्होंने निजी तौर पर प्रधानमंत्री के समक्ष यह बात रखी हो कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करने के लिए नागरिक समाज पर बेजा हमले करने से निवेशकों को आश्वस्त करने में शायद ही मदद मिलेगी। शायद उन्होंने यह भी कहा हो कि पुलिस के अपना दायित्व निभाने के बजाय राजनीतिक आकाओं के प्रति झुकाव दिखाने से वे लोग परेशान हो रहे हैं जो अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं?

हालांकि इस तरह की बातें कही जाने की संभावना बेहद कम ही हैं। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि जोरदार तालियां बजाने के प्रधानमंत्री के अनुरोध को एसोचैम सम्मेलन में मौजूद कारोबारियों ने एक नहीं बल्कि दो बार पूरे जोश से पूरा किया।

क्या उन्होंने पूर्वानुमेय नीतिगत पथ की तत्काल जरूरत को लेकर प्रधानमंत्री को कोई सलाह दी? या फिर किसी ने यह कहा कि तीन साल पहले बिना किसी चेतावनी के अचानक ही 80 फीसदी नोट वापस लेने से इतनी समस्याएं हुई थीं कि आज भी उसका असर महसूस हो रहा है? या, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक बदलाव के लिए एक साल की अग्रिम समयसीमा पर जोर देने से न तो कारोबारियों को फायदा हुआ है और न ही सरकार का राजस्व संग्रह ही बढ़ा है? या 'सशक्त रुपये' के लिए मजबूत मांग निर्यातकों के लिए मददगार नहीं रही है क्योंकि यह संरक्षणवाद की तरफ ले जाता है?

ऐसा होना संभव है लेकिन इसकी संभाव्यता कम है। एसोचैम बैठक की प्रतिक्रियाओं से यही लगता है कि कारोबार जगत सरकार से अर्थव्यवस्था को राहत देने की मांग कर रहा है क्योंकि सितंबर में घोषित कॉर्पोरेट कर कटौती से बात नहीं बन पाई है। इस तरह बहुत मुश्किल गुजरे साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को निर्मला सीतारमण ने 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ढांचागत निवेश योजना की घोषणा कर दी। किसी को भी नहीं मालूम है कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे और न ही ढांचागत परियोजनाओं से जुड़े शुरुआती अवरोधों को दूर करने के तरीके बताए गए हैं। जो भी हो, जब सरकार के सामाजिक एजेंडा को नागरिक समाज रूपी अवरोध से टकराना पड़ रहा है तब यह ऐलान एक अच्छा प्रदर्शन है।

फिर भी, वर्ष 2014 के सुहाने दिनों से विषमता साफ दिखती है। उस समय कारोबारी नेता मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे तमाम निवेश आयोजनों में उत्साह से हिस्सा लेते थे और प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे। यह सबकुछ सारे टीवी चैनलों पर खुले दिल से प्रचारित किया जाता था।

लेकिन अब होने वाली ये बैठकें बंद दरवाजों के भीतर होती हैं और वहां होने वाली चर्चा के मुद्दे भी गोपनीय होते हैं। इसका मतलब है कि अपने कूटनीतिक अंदाज में भी कारोबारी प्रमुखों के पास अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के बारे में कुछ अच्छा कहने के लिए बहुत बातें ही हैं।

ये कारोबारी नेता भारतीय समाज के विकास-पथ को लेकर भले ही अधिक फिक्र न करते हों लेकिन उन्हें यह बात समझनी ही होगी कि सत्ता के समक्ष सच्ची बात कहने से बचने का नुकसान खुद उनके कारोबार को भी उठाना होगा।

कानाफूसी

इनाम की बारी

मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को जल्दी ही नए वर्ष का उपहार मिल सकता है। पार्टी राज्य में विभिन्न बोर्ड और निकायों के अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान उन नेताओं के नाम पर शायद ही विचार हो जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टिकट दिया गया था। इसके बजाय पार्टी उन नेताओं को प्राथमिकता दे सकती है जो 15 वर्ष तक सत्ता से बाहर रहते हुए लगातार पार्टी के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें केके मिश्रा, शोभा ओझा और पंकज चतुर्वेदी हैं। पार्टी का राज्य और केंद्रीय नेतृत्व गुटबाजी से वाकिफ और चिंतित हैं क्योंकि इन नियुक्ति के बाद गुटबाजी और गंभीर हो सकती है। पार्टी महासचिव दीपक बाबरिया ने मुख्यमंत्री कमल नाथ से मुलाकात कर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच बेहतर तालमेल बिठाने को कहा है।

दोनों का फायदा

अफसरशाहों का निजी कंपनियों में शामिल होना कोई नई बात नहीं है लेकिन दागदार छवि वाले अधिकारियों का कर्ज में फंसी कंपनी में शामिल होना और उसका कायापलट कर देना अवश्य चकित करने वाली बात है। एक आईएएस अधिकारी जिनके खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वत का मामला था, ने अपने राज्य में सत्ता बदलने के बाद इस्तीफा दे दिया और उनके खिलाफ नई सरकार कोई मामला शुरू करती इससे पहले ही उन्होंने एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कंपनी ने उन पर लगे दाग के बावजूद उन्हें अपने बोर्ड में शामिल किया। शायद ऐसा करते वक्त उनके पुराने अनुभव और संपर्कों का ध्यान रखा गया हो। एक प्रतिस्पर्धी ने कहा कि भले ही ऐसा हो लेकिन इस आधार पर कोई उनका आकलन नहीं करने वाला। बहरहाल जो भी हो, कहा जा सकता है कि कंपनी और अफसरशाह दोनों फायदे में रहे।

आपका पक्ष

गलती किसी की, सजा आम जनता को

केंद्र सरकार ने पिछले साल किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत किसानों को साल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाने का प्रावधान है। देश के सभी राज्यों में इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों को मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में इस योजना की किस्त से संबंधित रोचक घटना पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से सामने आई है। दरअसल पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में किसानों को इस योजना का लाभ लेने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों का नामांकन किया जा रहा था। उस वक्त किसानों का नाम अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। इस योजना के लिए पीएम किसान पोर्टल में नामांकन करना होता है। इस पोर्टल की इनपुट भाषा अंग्रेजी है। ऐसे में 'उत्तम' नाम के एक किसान का नाम ऑनलाइन रूप में

'बेस्ट' दिखाई पड़ा। इसी प्रकार 'सुतार' नाम 'कारपेंटर' में बदल गया। 'भगवान' नाम का अनुवाद 'लॉर्ड' हो गया। एक किसान जिनका नाम 'माली' था वह 'गार्डनर' में तब्दील हो गया। मीडिया में आई खबरों के अनुसार इससे जुड़े अधिकारी ने कहा कि बैंक खाता संख्या और आधार विवरण के आधार पर किसानों को

सरकारी दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र या आधार में नाम, पते की प्रविष्टि सही हो

खाते में राशि जमा कराई गई है। उन्होंने कहा कि यह डेटा प्रविष्टि की खामी थी जिसे सुधारा जा रहा है। बहरहाल सरकारी योजनाओं में अगर ऐसी समस्या आती है तो इसके लाभार्थियों के लिए यह परेशानी का सबब बन जाता है। देश में जिस प्रकार की सरकारी आंकड़ों की प्रविष्टि होती है उसमें नाम गलत होने, पता का गलत होना, जन्मतिथि का गलत होना आम बात है। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड यहां तक कि पैन कार्ड में कुछ गलतियां निकल आती हैं जिसे बाद में सुधारा जाता है। इसे सुधारने में लोगों को अलग से परेशानी उठानी पड़ती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो ऐसी गलतियां ऑपरेटरों द्वारा होती हैं जो सही नाम, पता, उम्र की प्रविष्टि नहीं कर पाते हैं जिसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अत: सरकार ऐसे कुशल ऑपरेटरों द्वारा ही ऐसे कार्य कराए जिससे लोगों को दोबारा परेशानी नहीं हो या फिर सरकार को कुशल एवं प्रशिक्षित ऑपरेटरों की ही बहाली करनी चाहिए।

गरिमा सिंह, नोएडा

बेरोजगार युवाओं को मौका देने की बारी

अगर सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटी बातों पर ध्यान दे तो कुछ हद तक इसमें कमी की जा सकती है। देश में कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनमें अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो अन्य कुछ विभागों में फिर से नौकरी के लिए दरवाजे खुले हैं। इसी तरह निजी क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था है। सरकार और निजी क्षेत्र को चाहिए कि वे सरकारी या निजी कंपनियों से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति जो पेंशन की सुविधा लेते हों उन्हें नौकरी देने के बजाय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान करें जो रोजगार पाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी विभाग से सेवानिवृत्त होते हैं और मोटी पेंशन लेते हैं, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वह न तो सरकारी और न ही किसी निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन करें, ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी करने का मौका मिल सके।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।